

रजिस्टर्ड नं० पी०/एस० एम० 14.



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (भसाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्यशासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, वीरवार, 1 सितम्बर, 1988/10 भाद्रपद, 1910

हिमाचल प्रदेश सरकार

HIMACHAL PRADESH VIDHAN SABHA SECRETARIAT

NOTIFICATION

Shimla-4, the 1st September, 1988

No. 1-39/88-VS.—In pursuance to rule 135 of the Rules of Procedure and Conduct of Business of the Himachal Pradesh Legislative Assembly, 1973, "The Himachal Pradesh Legislative

Assembly (Allowances and Pension of Members) (Second Amendment) Bill, 1988 (Bill No. 10 of 1988)" having been introduced on the 1st September, 1988 in the Himachal Pradesh Vidhan Sabha, is hereby published in the Gazette.

LAXMAN SINGH,
Secretary.

1988 का विधेयक संख्यांक 10

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988

(विधान सभा में यथा पुरःस्थापित)

हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971
(1971 का 8) में और संशोधन करने के लिए विधेयक ।

भारत गणराज्य के उनतालीसवें वर्ष में हिमाचल प्रदेश विधान सभा द्वारा निम्न-
लिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

1. इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन). (द्वितीय संशोधन) अधिनियम, 1988 है । संक्षिप्त नाम

2. हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) अधिनियम, 1971 की धारा 4 में शब्द "पचहत्तर" के स्थान पर, जहां भी यह आया है, "एक सौ" शब्द प्रतिस्थापित किए जाएंगे । धारा 4 का संशोधन ।

1971 का

8

उद्देश्यों और कारणों का कथन

मूल्यों में अत्यधिक वृद्धि के कारण यह युक्तियुक्त समझा गया है कि विधायकों को अनुजेय विराम/दैनिक भत्ते को 75/- रुपए से बढ़ा कर 100/- रुपए प्रतिदिन कर दिया जाए।

विधेयक उपर्युक्त उद्देश्य की पूर्ति के लिए है।

शिमला :

1 सितम्बर, 1988.

वीरभद्र सिंह,
मुख्य मन्त्री।

वित्तीय ज्ञापन

प्रस्तावित विधेयक के खण्ड 2 के अधिनियमित होने पर, आसीन विधायकों को अनुजेय विराम/दैनिक भत्ते को पचहत्तर रुपए से एक सौ रुपए प्रति दिन करने पर प्रतिवर्ष, तीन लाख पचहत्तर हजार रुपए का अतिरिक्त आवर्ती व्यय अन्तर्विलित होगा। :

प्रत्यायोजित विधान सम्बन्धी ज्ञापन

—शून्य—

भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन राज्यपाल की सिफारिश

[सचिका सं० जी० ए० डी० (पी० ए०) 4 (डी)-17/88]

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश विधान सभा (सदस्यों के भत्ते और पेन्शन) (द्वितीय संशोधन) विधेयक, 1988 की विषयवस्तु के बारे में सूचित किए जाने के पश्चात् भारत के संविधान के अनुच्छेद 207 के अधीन उक्त विधेयक को विधान सभा में पुरःस्थापित करने और उस पर विचार करने की सिफारिश करते हैं।

(Authoritative English text of the Himachal Pradesh Vidhan Sabha (Sadasyon ke Bhatte aur Pension) (Dvitiya Sanshodhan) Vidheyak, 1988 (1988 ka Vidheyak Sankhyank 10) as required under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India.)

Bill No. 10 of 1988.

**THE HIMACHAL PRADESH LEGISLATIVE ASSEMBLY
(ALLOWANCES AND PENSION OF MEMBERS)
(SECOND AMENDMENT) BILL, 1988**

(AS INTRODUCED IN THE LEGISLATIVE ASSEMBLY)

A

BILL

further to amend the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) Act, 1971 (Act No. 8 of 1971).

BE it enacted by the Legislative Assembly of Himachal Pradesh in the Thirty-ninth Year of the Republic of India as follows:—

1. This Act may called. the Himachal Pradesh Legislative Assembly Short title.
(Allowances and Pension of Members) (Second Amendment) Act, 1988.

2. For the word “seventy-five” wherever it occurs in section 4 of the Amendment
Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of of section 4.
Members) Act, 1971, the words “one hundred” shall be substituted.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS

In view of the steep rise in prices, it has been considered reasonable that halting/daily allowance, as is admissible to the Legislators, be increased from Rs. 75/- to Rs. 100/- per day.

The Bill seeks to achieve the aforesaid objective: .

SHIMLA:
The 1st September, 1988.

VIRBHADRA SINGH,
Chief Minister.

FINANCIAL MEMORANDUM

Clause 2 of the proposed Bill when enacted will involve an additional recurring expenditure of Rs. 3.75 lakh per annum on account of the increase in the halting/daily allowance admissible to sitting M.L.As. from Rs. 75/- to Rs. 100/- per day.

MEMORANDUM REGARDING DELEGATED LEGISLATION

Nil

**RECOMMENDATIONS OF THE GOVERNOR UNDER ARTICLE 207 OF THE
CONSTITUTION OF INDIA**

[File No. GAD(PA)-4(D)-17/88]

The Governor of Himachal Pradesh, having been informed of the subject-matter of the Himachal Pradesh Legislative Assembly (Allowances and Pension of Members) (Second Amendment) Bill, 1988, recommends, under Article 207 of the Constitution of India, the introduction and consideration of the Bill in the Legislative Assembly.